RAJNIC
An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN
Digital India
Power To Empower
आज़ादी का अमृत महोत्सव
त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (अप्रैल से जून 2026)

हमारी विरासत

किराडू मंदिर

https://www.tourism.rajasthan.gov.in/barmer.html

किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित सबसे शानदार ऐतिहासिक और धरोहर स्थलों में से एक हैं। बाड़मेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित ये प्राचीन मंदिर अपनी उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी और अनोखी वास्तुकला शैली के लिए जाने जाते हैं। अपनी कलात्मक सुंदरता और बारीक मूर्तिकला के कारण, किराडू मंदिरों को अक्सर "राजस्थान का खजुराहो" कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर 11वीं और 12वीं सदी में परमार वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। मूलतः इस मंदिर परिसर में पाँच मंदिर थे, जिनका निर्माण सोलंकी (मारू-गुर्जर) वास्तुकला शैली में बनाया गया था। जो मध्यकाल में पश्चिमी भारत में लोकप्रिय थी। इनमें से भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी अवस्था में संरक्षित मंदिर है।

यह मंदिर अपनी बारीक पत्थर की नक्काशी, खूबसूरती से सजाए गए खंभों और कलात्मक छतों के लिए मशहूर है। दीवारों पर देवी-देवताओं, नर्तकियों, जानवरों और दैनिक जीवन के दृश्यों की विस्तृत मूर्तियाँ बनी हैं, जो उस दौर की उत्कृष्ट शिल्पकलाऔर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। कई सदियों बाद भी, ये नक्काशी अपनी सुंदरता और बारीकी से पर्यटकों को प्रभावित करती है। किराडू मंदिरों से जुड़ी एक प्रचलित स्थानीय लोककथा भी है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, एक ऋषि ने पास के गाँव को श्राप दिया था, और कहा जाता है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर के पास रुकता है, वह पत्थर में परिवर्तित हो सकता है। इस रहस्यमयी कहानी के कारण, सूर्यास्त के बाद ये क्षेत्र शांत हो जाता है और ज़्यादातर पर्यटक सूर्यास्त से पहले ही चले जाते हैं।

किराडू मंदिरों तक बाड़मेर शहर से आसानी से पहुँचा जा सकता है, जो जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर जैसे बड़े शहरों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सबसे नज़दीकी बड़ा हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो बाड़मेर से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। बाड़मेर से पर्यटक मंदिर परिसर तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगिस्तान के शांत नज़ारों से घिरे ये मंदिर पर्यटकों को इस इलाके के शानदार अतीत की एक अनोखी झलक दिखाते हैं और राजस्थान की सबसे प्रचलित कम चर्चित धरोहर स्थलों में से एक बने हुए हैं।

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत डीबीटी का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और पाली सहित पूरे भारत के कई राज्य और ज़िले जुड़े। इस कार्यक्रम में श्रम और रोज़गार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी शामिल हुईं और उन्होंने योजना के प्रभाव पर प्रकाश डाला। यह घोषणा की गई कि ₹2400 करोड़ के प्रोत्साहन (Incentives) वितरित किये गए हैं, जिससे रोज़गार के नए अवसरों के ज़रिए लगभग 15 लाख लोगों को लाभ हुआ है। यह योजना पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सीधे आर्थिक मदद और अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने वाले संस्थानों को मासिक प्रोत्साहन देती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा श्रम-शक्ति वाले सेक्टर पर खास ध्यान दिया जाता है। NIC ज़िला केंद्रों ने भरोसेमंद टू-वे लीज़्ड-लाइन कनेक्टिविटी स्थापित करके, VC इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात और टेस्ट करके, और व्यापक ऑन-साइट तकनीकी सहायता प्रदान करके कार्यक्रम के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई। उनकी समन्वित कोशिशों ने राज्य के सभी तय स्थानों पर निर्बाध कनेक्टिविटी और बिना किसी रुकावट के भागीदारी सुनिश्चित की।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19वें रोजगार मेले का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को 19वें रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने नए चुने गए उम्मीदवारों को संबोधित किया और भारत सरकार के आठ मंत्रालयों और विभागों (जिनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य सरकारी संगठन शामिल हैं) के सफल आवेदकों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। राजस्थान में यह कार्यक्रम जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में एक साथ आयोजित किया गया और सभी जगहों को राष्ट्रीय कार्यक्रम से वर्चुअली जोड़ा गया। जयपुर में रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव; जयपुर शहर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा और सिविल लाइंस के विधायक श्री गोपाल शर्मा की मौजूदगी में लगभग 420 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), राजस्थान ने डॉ. गायत्री पांडुरंगी (SIO राजस्थान), श्री अमित भिवानी (ASIO) और श्री हरि नारायण मीणा (VC कोऑर्डिनेटर) के मार्गदर्शन में निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) कनेक्टिविटी और एंड-टू-एंड तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया। NIC के जिला केंद्रों ने भरोसेमंद टू-वे लीज्ड-लाइन कनेक्टिविटी स्थापित करने, VC इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने और टेस्ट करने, तथा ऑन-साइट तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पूरे राज्य में कार्यक्रम का आयोजन सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से ₹511 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव (रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT) और श्री भूपेंद्र यादव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन) के साथ मिलकर ₹511 करोड़ से अधिक लागत वाली महत्वपुर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में ₹111 करोड़ के निवेश से अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और भिवाड़ी में लगभग ₹400 करोड़ की परियोजनाएं (जिनमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहल भी शामिल है) शामिल थीं। अलवर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा, विधायक श्री सुखवंत सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधियों और प्रशासनिक नेतृत्व की बड़ी भागीदारी देखी गई। NIC ने इस कार्यक्रम के लिए निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इसकी तकनीकी सहायता से नई दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न स्थानों के बीच सुचारू वर्चुअल संवाद संभव हो सका, जिससे गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों ने एक साथ उद्घाटन समारोह को देखा। ये परियोजनाएं आधुनिक बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और डिजिटल गवर्नेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती हैं और भारत की विकास यात्रा में राजस्थान की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करती हैं।

RAJNIC
An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN
Digital India
Power To Empower
NIC
त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (अप्रैल से जून 2026)

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

राजस्थान के समस्त जिलों में PM RAHAT के सफल कार्यान्वयन में एन.आई.सी का तकनीकी सहयोग

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की 22वीं बैठक 12 जून 2026 को सचिवालय में माननीय उपमुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य और NIC के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चाओं में भाग लिया और राज्य भर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संचालित पहलों की समीक्षा की। NIC की प्रस्तुति में दिखाया गया कि कैसे eDAR (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) प्लेटफ़ॉर्म को PM RAHAT (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार) के साथ जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्टिंग डिजिटल रूप से कैशलेस चिकित्सा देखभाल से जुड़ जाती है। यह नवाचार यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना का विवरण वास्तविक समय (real-time) में दर्ज हो और तुरंत चिकित्सा सहायता शुरू हो जाए, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण "गोल्डन आवर" के दौरान जान बचाना है। PM RAHAT योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष ज़ोर दिया गया। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि राज्य और ज़िला स्तर पर नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना के हर पीड़ित को बिना किसी देरी के कैशलेस उपचार मिल सके। विभागों से आग्रह किया गया कि वे आपसी तालमेल से काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ पीड़ितों तक तुरंत और समान रूप से पहुँचे। बैठक में सड़क सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और समय पर चिकित्सा सहायता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीक और प्रशासन मिलकर लोगों की जान बचाने और सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए काम करें।

राज्य स्तरीय जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यशाला: नवाचार, समन्वय एवं क्षमता संवर्धन की दिशा में पहल

जयपुर के राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में 27-28 अप्रैल 2026 को जिला सूचना विज्ञान अधिकारीयों (DIOs), अति. जिला सूचना विज्ञान अधिकारीयों, जिला सूचना विज्ञान सहयोगी और नएनियुक्त अधिकारियों के लिए दो दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के प्रमुख IT प्रोजेक्ट्स, उभरती हुई तकनीकों, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा और प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना था। इसमें कुल 42 NIC अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें 12 राज्य-स्तरीय और 30 जिला-स्तरीय अधिकारी शामिल थे। उद्घाटन सत्र में NIC राजस्थान की उपमहानिदेशक (DDG) एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (SIO)डॉ. पी. गायत्री, राजस्थान के स्टेट राज्य समन्वयक एवं DDG श्री नवीन कुमार और NIC के महानिदेशक (DG) श्री V.T.V. रमन्ना ने संबोधन दिया। DG ने 1976 में अपनी स्थापना के बाद से NIC की यात्रा का विवरण दिया, 50 साल पूरे होने पर NIC अधिकारियों को बधाई दी और AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग को अपनाते हुए NIC 2.0 के तहत अधिकारियों की बदलती जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, बैंडविड्थ बढ़ाने और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तथा साइबर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दो दिनों के दौरान, प्रतिभागियों ने ब्लॉकचेन, जियोस्पेशियल सेवाओं, साइबर सुरक्षा, (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) AI-आधारित एप्लिकेशन और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर तकनीकी सत्रों में भाग लिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डिजिटल ब्लूप्रिंट जैसी केस स्टडीज़ के साथ-साथ राजस्थान के प्रमुख प्रोजेक्ट्स जैसे शाला दर्पण, भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, लेबरसॉफ्ट (LabourSoft), ई-पंजीयन, PDS, ई-ट्रांसपोर्ट और ई-हॉस्पिटल को भी प्रदर्शित किया गया। सत्रों में सामान्य प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियाँ और एप्लिकेशन सुरक्षा प्रथाओं को भी शामिल किया गया। यह कार्यशाला ज्ञान साझा करने का एक व्यापक मंच साबित हुई, जिसने NIC राजस्थान के अधिकारियों को बदलती तकनीकी प्रणालियों और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया। NIC की नेटवर्क और तकनीकी सहायता टीमों ने निर्बाध हाइब्रिड भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे बिना किसी रुकावट के प्रेजेंटेशन और चर्चाएँ संभव हो सकीं। कार्यक्रम का समापन अधिकारियों से 'नागरिक-प्रथम' दृष्टिकोण अपनाने, परिचालन अनुशासन को मजबूत करने और निरंतर कौशल उन्नयन व नवाचार के माध्यम से NIC के मिशन में सक्रिय रूप से योगदान करने के आह्वान के साथ हुआ।

NIC के तकनीकी सहयोग से अंबेडकर जयंती पर ऐतिहासिक DBT हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में, 14 अप्रैल 2026 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की एक अहम पहल की। NIC द्वारा विकसित 'पे-मैनेजर' सिस्टम का इस्तेमाल करके, पूरे राज्य में कुल ₹1,328 करोड़ की राशि आसानी से वितरित की गई। इसमें से लगभग ₹1,110 करोड़ की राशि करीब 91 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों तक पहुँची, जबकि ₹218 करोड़ की राशि से 8.4 लाख 'पालनहार' योजना के लाभार्थियों को मदद मिली। यह बड़ा निधि हस्तांतरण न केवल सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों तक लाभों को पारदर्शी और समय पर पहुँचाने में NIC की अहम भूमिका को भी उजागर करता है।

डिजिटल भू-अभिलेख सेवाओं को मिली नई गति: अपनाखाता ऐप के 1 लाख+ डाउनलोड

अपनाखाता मोबाइल ऐप ने Google Play Store पर 1 लाख डाउनलोड का आँकड़ा पार कर लिया है और उपयोगकर्ता से इसे शानदार 4.5 रेटिंग मिली है। यह उपलब्धि ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे जानकारी तक आसान और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित होती है। अपनाखाता की सफलता NIC राजस्थान से मिले मज़बूत तकनीकी सहयोग को दर्शाती है, जो राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और नागरिकों पर केंद्रित सेवा वितरण को मज़बूत बना रहा है।

शालादर्पण शिक्षक ऐप: 5 लाख डाउनलोड के साथ डिजिटल शिक्षा में नई उपलब्धि

शालादर्पण प्रोजेक्ट के तहत NIC राजस्थान द्वारा विकसित शिक्षक ऐप ने Google Play Store पर 5 लाख डाउनलोड का अहम मुकाम हासिल किया है। राजस्थान भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सशक्त बनाने वाला यह ऐप रोज़ाना छात्रों की हाज़िरी, ऑनलाइन असेसमेंट और बेहतर शैक्षणिक निगरानी मॉनिटरिंग में मदद करता है। यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाती है और प्रौद्योगिकी पर आधारित टीचिंग सपोर्ट को मज़बूत करने में NIC राजस्थान और शिक्षा विभाग की मिली-जुली कोशिशों को दर्शाती है।

साइबर सुरक्षा सुझाव

यह न मानें कि आप खास हैं।

याद रखें: अगर कोई ऑफ़र सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे, तो अक्सर वह वैसा होता नहीं है। सावधान रहें, सोर्स की जाँच करें और खुद को इस जाल में फँसने से बचाएँ।

RAJNIC
An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN
त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (अप्रैल से जून 2026)

महत्वपूर्ण आयोजन / घटनाएँ

ए. एस.आई.ओ (जिले) का पाली–सिरोही दौरा: परियोजनाओं, ICT सेवाओं एवं IT अवसंरचना की व्यापक समीक्षा

श्री अनिल पुरोहित, ASIO (जिले), ने ज़िला केंद्रों में संचालित गतिविधियों एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 11 जून 2026 को NIC ज़िला केंद्र पाली और 12 जून 2026 को NIC ज़िला केंद्र सिरोही का दौरा किया। दोनों दौरों के दौरान, चल रही परियोजनाओं की प्रगति, हार्डवेयर से संबंधी समस्याओं और ICT-आधारित सेवाओं की डिलीवरी को और बेहतर बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के हिस्से के तौर पर, श्री पुरोहित ने मौजूदा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने और संचालन की पूर्ण तत्परता सुनिश्चित करने हेतु दोनों जगहों पर NIC VC कक्ष और जिला केंद्र के सर्वर रूम का निरीक्षण किया। इन दौरों से केंद्रों की तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने और सेवा डिलीवरी व परियोजना कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की रणनीतियों पर पर विचार विमर्श किया गया। पाली के दौरे के दौरान, श्री पुरोहित ने ज़िला सूचना अधिकारी के साथ, पाली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) श्री बजरंग सिंह (RAS) से भी मुलाकात की। यह बैठक राजस्व विभाग की परियोजनाओं से जुड़ी नई पहलों पर केंद्रित रही और इसमें जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस पहलों को आगे बढ़ाने और डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करने में ज़िला प्रशासन के साथ NIC के लगातार सहयोग पर जोर दिया गया।

फाउंडेशन बैच के RAS अधिकारियों के लिए संवादात्मक सत्र आयोजित

श्री विपिन खन्ना, वरिष्ठ निदेशक (IT) ने 15 मई 2026 को HCM RIPA, उदयपुर में कमर्शियल टैक्स सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस और RTS के RAS अधिकारियों के फाउंडेशन बैच के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। इस सेशन का मुख्य केंद्रबिंदु इनोवेटिव ICT पहलों और ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ज़रिए राज्य और ज़िला प्रशासन में डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करने में NIC की भूमिका पर था। अधिकारियों को विभिन्न सरकारी विभागों को NIC से मिलने वाले तकनीकी और परिचालनात्मक सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, प्रमुख IT पहलों और खास ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स पर भी प्रकाश डाला गया ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे टेक्नोलॉजी पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और नागरिकों पर केंद्रित सेवा वितरण को बेहतर बना रही है।

इस सत्र से ट्रेनी अधिकारियों को प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली और डिजिटल गवर्नेंस व जन-सेवा वितरण को आगे बढ़ाने में सरकार के प्रमुख प्रौद्योगिकी सहभागी के तौर पर NIC की भूमिका की पुष्टि हुई।

PCTS 2.0: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्यशाला

जयपुर में PCTS 2.0 पर एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका मकसद प्रेग्नेंसी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप उन्नत करने पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में NIC राजस्थान की राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी डॉ. गायत्री पांडुरंगी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, NIC के विशेषज्ञ एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। 2008 में प्रारंभ किया गया, PCTS लगभग दो दशकों से मां और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर रहा है। बदलती ज़रूरतों को देखते हुए, अब इसे PCTS 2.0 के तौर पर पुनः विकसित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप एक विस्तार योग्य प्लेटफॉर्म है। यह सिस्टम गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नाम-आधारित ट्रैकिंग की सुविधा देता है, जिसमें प्रसव-पूर्व देखभाल, प्रसव, प्रसव-बाद देखभाल, टीकाकरण और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की निगरानी शामिल है। यह RCH, HMIS, आयुष्मान भारत, राजहेल्थ, शाला दर्पण और जन आधार जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है। इसकी मुख्य विशेषताओं में जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, लाडो इंसेंटिव स्कीम, मां वाउचर स्कीम की निगरानी और 500 से ज़्यादा पैरामीटर्स की मासिक प्रतिवेदन शामिल है। कार्यशाला में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि PCTS 2.0 फील्ड वर्कर्स के लिए ऐप्स को आसान बनाएगा, एक एकीकृत डैशबोर्ड देगा और पूरे राजस्थान में मां और बच्चे की सेहत से जुड़े नतीजों को बेहतर बनाएगा।

नवनियुक्त पटवारियों के क्षमता निर्माण हेतु NIC जिला केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित

नव-नियुक्त हुए पटवारियों के लिए 15 मई 2026 को पटवार ट्रेनिंग स्कूल (PTS), कोटा में और 20 मई 2026 को ज़िला परिषद हॉल, उदयपुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद प्रौद्योगिकी पर आधारित रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (राजस्व प्रशासन) के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाना था, जिसके लिए मुख्य डिजिटल लैंड रिकॉर्ड एप्लीकेशन—ई-धरती, भू-नक्शा और अपना खाता—पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को इन अनुप्रयोगों के मुख्य कामों, जैसे लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, म्यूटेशन प्रोसेसिंग और कैडस्ट्रल मैपिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रैक्टिकल डेमो और इंटरैक्टिव सेशन के ज़रिए, ट्रेनिंग लेने वालों ने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए ज़रूरी तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल हासिल किए। यह पहल राजस्व कर्मचारियों की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस समाधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करने के लिए NIC राजस्थान की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिससे ज़्यादा पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन में योगदान मिलता है।

एन.आई.सी. राजसमंद ने विकसित किया रिफॉर्मेटिव न्यूज़ मॉनिटरिंग सिस्टम (RNMS) पोर्टल

समाचार पत्रों एवं डिजिटल मीडिया में प्रकाशित होने वाली ज़िले-स्तर की सुधार और विकास से जुड़ी खबरों की निगरानी और प्रबंधन को अधिक प्रभावित बनाने के लिए, राजसमंद के ज़िला कलेक्टर के मार्गदर्शन में NIC ज़िला केंद्र, राजसमंद ने रिफॉर्मेटिव न्यूज़ मॉनिटरिंग सिस्टम (RNMS) विकसित किया है। यह प्रणाली मीडिया रिपोर्ट को ट्रैक करने, समय पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने और प्रभावी प्रशासनिक समीक्षा के लिए एक केंद्रीकृत, सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफ़ॉर्म देता है। PHP, MySQL, HTML5, CSS3 और JavaScript जैसी ओपन-सोर्स तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाए गए RNMS में रोल-बेस्ड यूज़र एक्सेस, विभाग-वार खबरों का असाइनमेंट, रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग, डैशबोर्ड एनालिटिक्स, ऑटोमेटेड प्रतिवेदन जनरेशन और लंबित मामलों के लिए नोटिफ़िकेशन सिस्टम जैसी सुविधाएँ हैं। यह एप्लीकेशन एक व्यवस्थित वर्कफ़्लो का पालन करता है, जिससे विभाग अनुपालन रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और हर प्रदान की गई खबर का वस्तुस्थिति अद्यतन कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक चरण पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है। RNMS के लागू होने से मीडिया रिपोर्ट की निगरानी को डिजिटल बनाकर प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसने पारदर्शिता बढ़ाई है, विभागीय जवाबदेही को मज़बूत किया है और जनता की शिकायतों व विकास से जुड़े मुद्दों पर समय पर कार्रवाई को संभव बनाया है। यह प्रणाली एक प्रभावी ई-गवर्नेंस समाधान के रूप में काम करता है, जो उत्तरदायी एवं देता आधारित जिला प्रशासन को सशक्त बनाता है।

RAJNIC
An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN
Digital India
Power To Empower
त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (अप्रैल से जून 2026)

त्रैमासिक प्रोजेक्ट: RAJPSP (राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल)

राज्य ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसकी निगरानी के लिए एक नई, पारदर्शी और पूरी तरह से ICT-आधारित व्यवस्था शुरू की है। इसमें राज्य भर के लगभग 36,000 निजी विद्यालय शामिल हैं। NIC राजस्थान द्वारा विकसित यह RAJPSP सिस्टम, वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों और उनके माता-पिता के लिए निजी विद्यालयों की एंट्री क्लास (शुरुआती कक्षाओं) में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा पाने का एकमात्र आधिकारिक ज़रिया है। इस समय, RAJPSP प्रणाली पर राज्य भर के 90 लाख से ज़्यादा छात्रों और 36,000 से ज़्यादा निजी विद्यालयों का सत्यापित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, जो इसे राज्य के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय शिक्षा प्रणालियों में से एक बनाता है।

RAJPSP सिस्टम विभाग को पूरे RTE संपूर्ण प्रक्रिया को मैनेज करने में व्यापक रूप से मदद करता है, जिसमें शामिल हैं:

- RTE के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन
- पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के जरिए सेंट्रलाइज़्ड प्रायोरिटी लिस्ट बनाना
- बच्चे की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और स्कूल-वाइज़ सीट अलॉटमेंट
- विभाग द्वारा बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन
- फीस रिइम्बर्समेंट के लिए स्कूलों द्वारा ऑनलाइन बिल बनाना
- स्कूलों को फीस का ऑनलाइन DBT

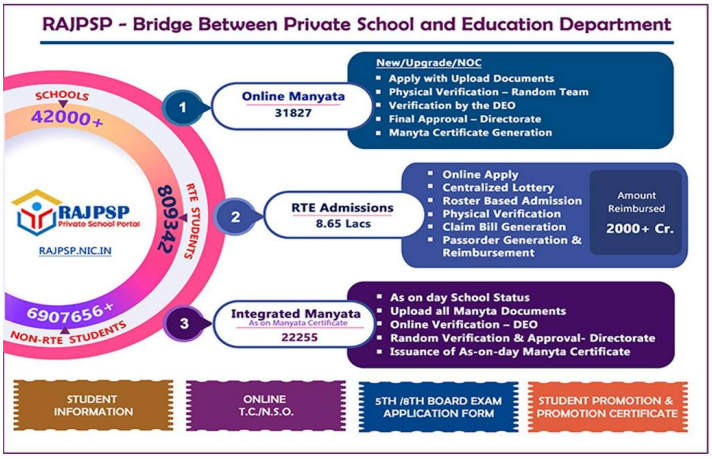

शुरुआत से ही, इस प्लेटफ़ॉर्म ने 2016 से RTE से जुड़े सभी आवेदनों और वर्कफ़्लो को लगातार ऑनलाइन प्रोसेस किया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस का एक नया मानक स्थापित हुआ है। अब तक, 12 लाख से ज़्यादा छात्र इस सिस्टम से लाभान्वित हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों को हर साल ₹1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पारदर्शी तरीके से रीइम्बर्स (वापस) की गई है।

RAJPSP प्रणाली संबंधित योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति सहायता भी देता है। वीर बाला काली बाई भील बालिका फीस रीइम्बर्समेंट योजना के तहत, कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली उन लड़कियों को फीस वापसी की सुविधा मिलती रहती है, जिन्हें पहले RTE के तहत प्रवेश मिला था। इसी तरह, RTE पृष्ठभूमि वाले कक्षा 9 से 12 के लड़के भी मुख्यमंत्री फीस रीइम्बर्समेंट योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे शुरुआती शिक्षा के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रहती है।

इस प्रोजेक्ट के नवाचार, बड़े पैमाने और असर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कारों से मान्यता मिली है, जिनमें CSI निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड (2013-14), SKOCH अवार्ड (2015) और शिक्षा के क्षेत्र में "बेस्ट ERP प्रोजेक्ट" के लिए 10वां eINDIA अवार्ड शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह समाधान पारदर्शी गवर्नेंस, समावेशी शिक्षा और प्रौद्योगिकी - आधारित सामाजिक समानता के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा है।

यह प्रणाली स्कूलों की मान्यता (मान्यता) के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधाएँ भी देता है, जिसमें नई मान्यता के लिए आवेदन, मौजूदा मान्यता को अपग्रेड करना और CBSE अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना शामिल है। इससे एक पारदर्शी, स्टैंडर्ड और डिजिटल रूप से मॉनिटर की जाने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

RAJPSP पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

- RTE के लिए एक ही आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म: यह 36,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों को कवर करने वाला एक एंड-टू-एंड, द्विभाषी ICT समाधान है। यह वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए RTE एक्ट, 2009 के तहत 25% मुफ़्त सीटों का लाभ उठाने का एकमात्र आधिकारिक माध्यम है।
- पारदर्शी और ऑटोमेटेड एडमिशन: ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्राथमिकता सूची बनाना, और लॉटरी के आधार पर सीट आवंटन; इसमें कई एंट्री क्लास, स्कूल के हिसाब से उम्र की पॉलिसी और उपयोगकर्ता के साथ लगातार बातचीत की सुविधा शामिल है।
- सत्यापित प्रतिपूर्ति और वित्तीय पारदर्शिता: डिजिटल जांच, ऑटोमेटेड क्लेम बिल बनाना, सीधे DBT रीइम्बर्समेंट, फ़ंड के इस्तेमाल की ट्रैकिंग और शिकायतों का समाधान; इससे 12 लाख से ज़्यादा छात्रों को फ़ायदा होता है और सालाना ₹1000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया जाता है।
- एकीकृत छात्रवृत्ति और पढ़ाई जारी रखने में मदद: वीर बाला काली बाई भील बालिका फ़ीस रीइम्बर्समेंट स्कीम और CM फ़ीस रीइम्बर्समेंट स्कीम को एक साथ जोड़ना, ताकि क्लास 9-12 के RTE छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके।
- बेहतर स्कूल गवर्नेंस और डेटा रिपॉज़िटरी: मान्यता (स्कूल रिकग्निशन) से जुड़ी सभी तरह की सेवाएँ, जैसे नई मान्यता, अपग्रेडेशन, CBSE NOC, और 90 लाख से ज़्यादा छात्रों के रिकॉर्ड का केंद्रीकृत डेटाबेस; इसे CSI, SKOCH और eINDIA अवॉर्ड्स से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

परियोजना टीम

पुरस्कार / सम्मान

श्री परमजीत सिंह को SmartPB असम एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया।

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This Certificate of Appreciation is officially awarded by the Office of the Chief Electoral Officer, Assam, to Shri Paramjeet Singh, DIO NIC, Sri Ganganagar for their outstanding work in developing the SmartPB Assam application. Their technical innovation has provided a robust, unified platform for the seamless management of Postal Ballots across the state.

By digitizing the tracking and issuance process, they have significantly enhanced the transparency and speed of electoral operations, ensuring that those on election duty and absentee voters can exercise their franchise effectively.

The Office of the Chief Electoral Officer commends their dedication to strengthening the democratic framework through digital excellence and recognizes this vital contribution to the successful conduct of elections in Assam.

Shri Anurag Goel, IAS
Chief Electoral Officer, Assam
Date: 06.05.2026

SmartPB Assam एप्लीकेशन के विकास में बेहतरीन योगदान के लिए, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 06 मई 2026 को NIC श्री गंगानगर ज़िला केंद्र के वैज्ञानिक-C और ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) श्री परमजीत सिंह को प्रशंसा प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया। SmartPB Assam एप्लीकेशन पूरे राज्य में पोस्टल बैलेट के सुचारू प्रबंधन के लिए एक मज़बूत और एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।

श्री सुशील कुमार अग्रवाल को PadAIwithAI एप्लिकेशन के लिए SKOCH पुरस्कार प्राप्त हुआ

NIC टोंक ज़िला केंद्र के वैज्ञानिक-C और DIO, श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए विकसित AI-आधारित इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म PadhAIwithAI को 20 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 108वें SKOCH समिट में ज़िला गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सरकारी स्कूलों में सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए AI के इनोवेटिव इस्तेमाल और डिजिटल गवर्नेंस व शिक्षा में बदलाव लाने में इसके अहम योगदान के लिए दिया गया।

परियोजना लेन-देन सांख्यिकी

SN	Project	Number of Transactions			Total Trans.
		Apr-26	May-26	Jun-26	
1	DBT through Pay Manager	11505852	12460136	11403923	35369911
2	DILRMP ROR	4398522	4326221	6223993	14948736
3	Shala Darpan	8324888	3368701	18772	11712361
4	IFMS - Rajkosh Challans	1559850	1551525	1693962	4805337
5	eGras	1321636	1309905	1413266	4044807
6	IFMS - Rajkosh Bills	483168	403998	296810	1183976
7	Pay Manager Other Bills	147052	123819	91105	361976
8	Registration and Stamps	218924	260946	272474	752344
9	E-Transport Vehicle Registration	150798	143940	133998	428736
10	E-Transport Driving Licence	57739	55512	52567	165818

RAJNIC
An e-Governance Newsletter of
NIC RAJASTHAN
Digital India
NIC
त्रैमासिक डिजिटल समाचार पत्र (अप्रैल से जून 2026)

प्रौद्योगिकी वार्ता: AI बनाम AI – साइबर युद्ध का भविष्य

श्री विकास कुमार
वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर-SB
ADIO, NIC बाड़मेर

जैसे-जैसे सरकारें और संगठन अपने डिजिटल बदलाव की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, साइबर खतरे ज़्यादा जटिल, स्वचालित और पता लगाने में मुश्किल होते जा रहे हैं। जरूरी सेवाओं, नागरिकों के डेटा और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म के ऑनलाइन होने के साथ, साइबर सुरक्षा अब सिर्फ़ IT से जुड़ी चिंता नहीं रह गई है—यह एक रणनीतिक ज़रूरत बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन ला रहा है और हमलावरों व बचाव करने वालों, दोनों को अभूतपूर्व क्षमताएँ दे रहा है। साइबर सुरक्षा का भविष्य तेज़ी से AI बनाम AI वाले माहौल में बदल रहा है, जहाँ स्मार्ट सुरक्षा सिस्टम मशीन की रफ़्तार से स्मार्ट साइबर खतरों का लगातार मुकाबला करते हैं।

AI: एक दोधारी तलवार:- साइबर अपराधी हमलों के दायरे, रफ़्तार और असर को बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। AI का इस्तेमाल कमज़ोरियों का पता लगाने, बहुत भरोसेमंद लगने वाले फ़िशिंग ईमेल बनाने, डीपफेक कंटेंट तैयार करने और ऐसे मैलवेयर बनाने में किया जा सकता है जो सुरक्षा उपायों के हिसाब से खुद को ढाल सकें। उदाहरण के लिए, कोई हमलावर AI का इस्तेमाल करके किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नाम से एक पर्सनलाइज़्ड फ़िशिंग ईमेल बना सकता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और बातचीत के तरीकों का विश्लेषण करके, यह मैसेज बहुत असली लग सकता है, जिससे उपयोगकर्ता के क्रेडेंशियल या संवेदनशील जानकारी के चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, सुरक्षा करने वाले भी साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक सुरक्षा उपकरण मुख्य रूप से पहले से तय नियमों और हस्ताक्षर पर निर्भर करते हैं, जबकि AI-आधारित सिस्टम नेटवर्क की गतिविधियों से सीख सकते हैं, असामान्यताओं की पहचान एवं खतरों का तुरंत जवाब दे सकते हैं।

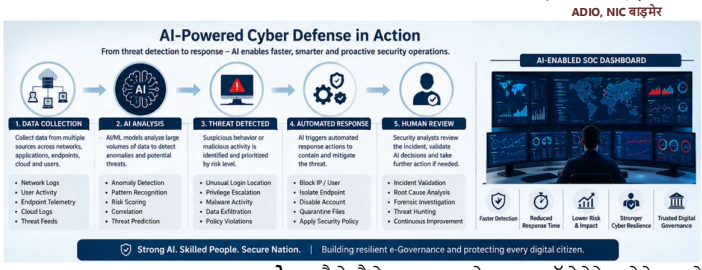

AI-संचालित साइबर सुरक्षा:- राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), जो ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस सेवाओं को सपोर्ट करता है, उसके लिए AI सरकारी प्रणाली और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा में बड़े फ़ायदे देता है। इसके मुख्य इस्तेमाल ये हैं:

- तत्काल में खतरों का पता लगाना और निगरानी – साइबर खतरों का तत्काल में पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी नेटवर्क और अनुप्रयोग की लगातार निगरानी करना।
- यूज़र और एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (UEBA) – यूज़र या सिस्टम की असामान्य गतिविधियों की पहचान करना, जो अनधिकृत एक्सेस, अंदरूनी खतरों या खाते के साथ छेड़छाड़ का संकेत हो सकती हैं।
- ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स – संदिग्ध गतिविधियों को अपने-आप रोकना, अलग या कम करके सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को तेज़ी से रोकना।
- प्रेडिक्टिव थ्रेट इंटेलिजेंस – नए साइबर खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने की तैयारी के लिए खतरे के रुझानों और खुफ़िया जानकारी फीड का विश्लेषण करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाना और पहचान की सुरक्षा धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन, किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश और अनधिकृत एक्सेस का पता लगाकर नागरिकों और संगठनों की पहचान की सुरक्षा करना।

एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के अकाउंट से अचानक कम समय में अलग-अलग दूर-दराज़ जगहों से कई बार लॉग-इन करने की कोशिश की जाती है। AI-सक्षम सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म तुरंत इस असामान्य गतिविधि की पहचान कर सकता है, संदिग्ध पहुँच को रोक सकता है और किसी बड़े नुकसान से पहले सुरक्षा दलों को अलर्ट कर सकता है। AI, सुरक्षा ऑपरेशन्स सेंटर्स (SOCs) की क्षमताओं को भी बेहतर बनाता है; यह नेटवर्क, अनुप्रयोग और क्लाउड एनवायरनमेंट में लाखों सुरक्षा घट्नाओं का विश्लेषण करता है, जिससे विश्लेषकों को ज़रूरी खतरों को प्राथमिकता देने व उन पर ज़्यादा कुशलता से कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

AI बनाम AI का उभरता हुआ युद्धक्षेत्र: - जैसे-जैसे साइबर खतरे ज़्यादा ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, भविष्य की साइबर लड़ाई में एक-दूसरे से मुकाबला करने वाले ऑटोनॉमस अटैकर और डिफेंडर सिस्टम शामिल हो सकते हैं। अटैकर AI लगातार कमज़ोरियों की पहचान करेगा और हमले की रणनीतियों को बेहतर बनाएगा, जबकि डिफेंडर AI सिस्टम की निगरानी करेगा, खतरों का अनुमान लगाएगा और रियल-टाइम में सुरक्षा उपाय लागू करेगा। हालांकि, AI इंसानी विशेषज्ञता का पूरी तरह से विकल्प नहीं है। एडवर्सीरियल अटैक (जानबूझकर किए गए हमले), गलत ट्रेनिंग डेटा और ऑटोमेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता जैसी चुनौतियां मज़बूत गवर्नेंस, इंसानी निगरानी और रणनीतिक फ़ैसले लेने की ज़रूरत को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष - AI साइबर सुरक्षा के स्वरूप को पूरी तरह से बदल रहा है। जैसे-जैसे हमलावर स्मार्ट प्रौद्योगिकीयाँ अपना रहे हैं, संगठनों को भी उतने ही उन्नत AI-आधारित सुरक्षा समाधानों के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। AI नवाचार को कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों, मजबूत नीतियों और लगातार निगरानी के साथ जोड़कर, संगठन ऐसे सुरक्षित, मजबूत व भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिकी प्रनिलियाँ बना सकते हैं जो साइबर खतरों की अगली पीढ़ी का सामना करने में सक्षम हों। साइबर युद्ध का भविष्य केवल इंसानों बनाम हैकर्स का नहीं होगा, बल्कि यह तेजी से AI बनाम AI का मुकाबला बन जाएगा, जिसमें इंसान रणनीति, गवर्नेंस व निगरानी प्रदान करेंगे।

Published By

संरक्षक
डॉ. पी. गायत्री, एस. आई. ओ. राजस्थान

संपादकीय बोर्ड
श्री दिलीप जैन, वैज्ञानिक-'ई'
श्री विनोद कुमार शर्मा , वैज्ञानिक-'ई'
श्री हेमंत मेहता, वैज्ञानिक-'ई'
श्री मनीष कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-'सी'
श्रीमती सोनिया तोमर, एसटीए-'ए'

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
राजस्थान राज्य केंद्र
8318, उत्तर-पश्चिम भवन
शासन सचिवालय,
जयपुर – 302005
0141-2227992
ईमेल: sioraj@nic.in
वेबसाइट: https://raj.nic.in

सेवानिवृति

नाम: महेंद्र सिंह कछवाहा
जन्म तिथि: 24.06.1966
कार्यग्रहण तिथि: 09.08.1996
कार्यग्रहण पद: वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-B (DIA), सिरोही
सेवानिवृत्ति तिथि: 30.06.2026 (सिरोही)
पदस्थापन स्थान: सिरोही, राजस्थान
शिक्षा: JNV यूनिवर्सिटी, जोधपुर M.Sc (सांख्यिकी)

नये सदस्यों का स्वागत

श्री आकाश जोशी
पद: वैज्ञानिक-B
पदस्थापन स्थान: NIC जयपुर
कार्यग्रहण तिथि: 29-06-2026

श्री देवका धर्मेंद्र
पद: वैज्ञानिक-E
पदस्थापन स्थान: NIC जयपुर
कार्यग्रहण तिथि: 01.07.2026

श्री अभिषेक आर. वछराजनी
पद: वैज्ञानिक-C
पदस्थापन स्थान: NIC डूंगरपुर
कार्यग्रहण तिथि: 01.07.2026

राजस्थान से स्थानांतरित

श्री अनिल पुरोहित, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री अजीत कुमार जैन, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री शेखर शुक्ला, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री अमित अग्रवाल, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री श्रीपाल यादव, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्रीमती अंजू मित्तल, वैज्ञानिक-F
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री अंकुर गोयल, वैज्ञानिक-E
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली

श्री प्रेम शंकर चौबीसा, वैज्ञानिक-E
NIC RSU, जयपुर (से)
NIC गुजरात

श्री मिलिंद कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-D
NIC राजसमंद (से)
NIC मुख्यालय, नई दिल्ली